origin of the employees are not maintained.

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा संचालित खानें

2944. **श्री गया सिंह:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा संचालित भवनाथपुर चूना-पत्थर (आर०एम०डी०) और यंत्रीकृत खानों में उत्पादन कब आरम्भ हुआ;

(ख) क्या उपरोक्त यंत्रीकृत खानों में उत्पादन पिछले दो सालों से लगभग ठप्प हो गया है और वहां की मशीनों और नियोजित बारह सौ श्रमिकों के पास कोई काम नहीं रह गया है; और

(ग) क्या यंत्रीकृत खानों के अधिकतम प्रयोग हेतु उनके पुनः सकीर्यकरण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) भवनाथपुर यंत्रीकृत चूना-पत्थर खान वर्ष, 1979 में चालू की गयी थी।

(ख) यह सच नहीं है कि नियोजित मशीनों और कामगारों के पास कोई काम नहीं है। भवनाथपुर की यंत्रीकृत खान में उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) प्रौद्योगिकीय दृश्यलेख में परिवर्तन होने के कारण इस्पात संयंत्र लौह निर्माण तथा इस्पात निर्माण के लिए बेहतर ग्रेड के चूना-पत्थर की मांग कर रहे हैं जिसके कारण भवनाथपुर चूना-पत्थर खान से कम माल उठाया जा रहा है। इस स्थिति में, भविष्य में इस्पात संयंत्रों में भवनाथपुर के चूना-पत्थर के अधिक इस्तेमाल करने के आसार बहुत कम हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के निकटवर्ती गांवों का विकास

2945. **श्री गया सिंह:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन बोकारो इस्पात संयंत्र के निकटवर्ती गांवों को विकसित करने हेतु क्या योजनाएं हैं;

(ख) संयंत्र प्रबन्धन द्वारा वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु स्थानीय और जिला प्रशासन को स्थायी तौर पर उपलब्ध कराये गये वाहनों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त वाहनों पर प्रतिमाह कितना व्यय किया जाता है; और

(घ) उक्त इस्पात संयंत्र द्वारा बिहार सरकार के पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आवंटित विभिन्न श्रेणियों की आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी-कितनी है और संयंत्र प्रबन्धन द्वारा इन आवासीय इकाइयों के रख-रखाव पर प्रतिमाह कितनी धनराशि व्यय की जाती है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार, बोकारो इस्पात संयंत्र के आस-पास के गांवों में चार आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की योजना है:—

1. शिक्षा —स्कूल इमारतों का प्रावधान करके।
2. पीने का पानी —रिग बोर हैंड पम्पों, नए कुएं खोदकर तथा पुराने कुओं की मरम्मत करके।
3. यातायात —गांव की सड़कों का विकास कर।
4. स्वास्थ्य केन्द्र —स्वास्थ्य केन्द्र बनवाकर तथा चलते-फिरते (मोबाइल) चिकित्सा कैंपों के जरिए निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके।

इसके अतिरिक्त, बेरोजगार युवकों तथा उनकी श्रमिक सहकारी समितियों को ठेके तथा कुक्कुट पालन आदि के माध्यम से स्वतः रोजगार प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) बोकारो के जिला प्रशासन (पुलिस/दंडाधिकारी आदि) को दी गई गाड़ियों की संख्या 69 है तथा उस पर मासिक व्यय 4.90 लाख रुपये से 5.45 लाख रुपये होता है।